



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राप्तिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

मं. ५०।

नई दिल्ली, मुध्यांशु, फरवरी २१, १९७९ / फाल्गुन २, १९००

No. ५०।

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 1979/PHALGUNA 2, 1900

इस भाग में विभिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह भाग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विभिन्न नाम और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

मंत्रालय

नई दिल्ली, २० फरवरी, १९७९

सं. ५/१/७९-सी०एस०-५—किसी अन्य अधिनियम की तरह ही कम्पनी अधिनियम, १९५६ भी केंद्रीय सरकार द्वारा उसको अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शब्दियों के अन्तर्गत जारी किए गए नियमों, आदेशों, अधिगच्छाओं और निर्देशों में निर्धारित माध्यम के द्वारा भाग् किया जाना है। अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नियम, कार्यों के द्वारा ही कार्यगत होते हैं, जो या तो अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रश्न का अनुमोदन अरते हुए नियंत्रण के लिये उपयोगी सूचना का प्राप्त साक्षात् या अधिनियम द्वारा अनुपालन के उपयोग का अभिलेख को रखते उद्देश्य के लिए अंदरित है। ऐसे नियम और कार्य अधिनियम के क्रियात्मक रूप से कार्य करने में गणदण्डन के रूप में महत्वपूर्ण है, जैसे कि कम्पनी के नाम परिवर्तन, पदिक लाइसेंट कम्पनी का प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में पार्टनरशिप, कम्पनी संविधान, गोदरों का हस्तातरण, प्रभारियों का सूचन, शेयरों वर्टिकल, उत्पीड़न और कुप्रबन्ध, कम्पनियों का निरीक्षण, कम्पनी का पुनर्नियोग, कम्पनी का समाप्ति, अधिलेखों को सुरक्षित रखना, विद्यो-कम्पनियों के अभिलेखों का अनुबाद, कोर्ट की अदायी आदि जैसे कम्पनी प्रशासन में अन्यादिक मामलों में विभिन्नियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत केंद्रीय सरकार को आवेदन पत्र देने या कम्पनी रजिस्ट्रार के पांच कार्यों और विवरणियों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को छोड़कर शेष पर प्रभावी होते हैं।

२. नियमों और कार्यों का पहला ममूल अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी (केंद्रीय सरकार) मासान्त्र नियम और कार्य, १९५६ द्वारा अधिसूचित किया गया था। इन नियमों के अन्तर्गत निर्धारित ६७ दूसरे कार्यों से अलग अधिनियम के प्रलंबित निर्धारित ३० अन्य नियमों के अन्तर्गत ४० अन्य कार्यों को लगभग निर्धारित किया गया है। कम्पनियों, विभिन्न व्यावसायों, वाणिज्य मंडलों और उद्योगों तथा अन्यों के द्वारा सभी सभी पर आलोचनाएं की गई हैं कि वहाँ से कार्य है, जिनमें से बहुत से कामानी में सुना किया जा सकता है और यहाँ तक कि जो अनिवार्य है, वे अपनी सम्बन्धेवा, शैली तथा आकार में काफी जटिल हैं और यहाँ नक्शे अपने भे स्पृष्टप्रयत्न युक्तिमंगल नहीं हैं या सुना मांगने के लिये विरल नहीं हैं तथा अधिनियम के उद्देश्यों के लिये प्रश्यक्षण रूप से सम्बन्धित नहीं हैं। इन सभी के मध्यमें यह कहा जाता है कि इनको शपते उपकर्मों और लागू करने में इनको काफी कठिनाइयाँ हुई हैं। विभिन्न नियमों के अन्तर्गत निर्धारित कार्यों की संबीक्षा करने का भासला बहुत पहले से ही चल रहा है तथा अभी तक इस पर विचार किया गया होना, किन्तु यह विशेषज्ञों में मुख्य संशोधन के लिये जो फरवरी, १९७५ से लागू हुए थे तथा उसके तुरन्त पश्चात् कम्पनी अधिनियम की संबीक्षा करने के लिये उच्चाधिकार विधेय समिति भी नियुक्ति के कारण नहीं हो सका। उच्चाधिकार विधेय समिति जिसमें विभिन्न वाणिज्य मंडलों, व्याकाशायिक निवायों का प्रतिनिधित्व था, ने भी अनुबव किया कि इन कार्यों की काफी संख्याओं में कभी और उसमें उल्लिखित अनावश्यक औरों में से कुछ को निकालने की काफी गुजाई है तथा यह सुझाव दिया कि कार्यों के परिशोधन का सामना मरकार द्वारा लिया जाना चाहिए। अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित

फार्मों में से कुछ में परिवर्तन भी किया जा सकता है अगर इस विशेषज्ञ समिति के सुझावों की अन्तिमता मरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है। अशापि, इस स्तर पर उस आकृति का पुरानुमान लगाना कठिन है जिसके अनुहय मरकार द्वारा समिति की सिफारिशों प्रतिम रूप से स्वीकार की जात्रें तथा यह परिणामी परिवर्तनों को समिति की सिफारिशों से सम्बद्ध अत्रेक नियमों के अन्तर्गत प्रपत्रों का, अन्ततः समावेश होता। उपरवर्णित कारणों से, इस अधिनियम के अन्तर्गत विहृत उप कार्मों, जिन के उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति के सिफारिशों के अनुसरण में परिवर्तित किए जाने की संभावना है, में भिन्न अन्य कार्यों का सर्वोमुखी पुनर्विलोकन करने के लिए एक समिति का गठन करना, आवश्यक हो गया है।

3. तदनुसार, मरकार कम्पनी प्रवित्तियम्, 1956 के प्रणामन मध्यवर्धी अपेक्षाओं के उत्तराधिकार के माध्यम साथ इसके प्रपत्रों को भरत तथा प्रभावी बनाने के लिये इसके तथा इसके अन्तर्गत नियमों, के अन्तर्गत विहित विषयाम विप्रतीर्थी को सम्बोधित करने व अपनी रिपोर्ट देने के लिये एन्डवारा एक समिति नियुक्त करती है।

4. यह समिति निम्न प्रकार से गठित होगी :—

श्री के० के० रे, आई० ए० एस० (प्रबकाश प्राण) —प्रधम

1. श्री ए० नीलकान्तन, संयुक्त सचिव (विधि) कम्पनी कार्य विभाग मध्यम
2. श्री बी० राजारमन, शास्त्र प्राप्ति लेखापाल, ठाकुर वैद्यनाथ अम्यर, ए०ष्ट कम्पनी मध्यम
3. श्री पी० आर० मुख्योपाध्याय, सचिव, इंडियन इंडस्ट्रीज नियमिटेड मध्यम
4. श्री ए० ए० चक्रवर्ती, संयुक्त निदेशक (विधि) कम्पनी कार्य विभाग मध्यम

5. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, एवं इसकी बैठकें आवश्यकतानुसार सम्पन्न होंगी। समिति की रिपोर्ट, भारत सरकार विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, (कम्पनी कार्य विभाग) को 30 जून 1979 तक प्रस्तुत की जायेगी।

आदेश

आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति सभी गोपनीयकारों, संघ सामिति अंत्रों, भारत सरकार के मंत्रालयों व विभागों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति के नियुक्त तथा सैनिक विधियों की भेजी जाय।

यह भी आदेश दिया कि इसे भारत के अमाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

पी० कृष्णमूर्ति सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

RESOLUTION

New Delhi, the 20th February, 1979

No. 5/1/79-CL. V.—The Companies Act, 1956, like any other statute, is administered through a set of rules, orders, notifications and directions issued by the Government under powers conferred by the Act itself. The rules framed under the Act are accompanied by forms which are designed either to elicit information useful for deciding any question of approval under the Act or is required for the purpose of keeping a record of compliance enjoined by the statute. These rules and forms are of critical importance in the practical working of the Act, affecting, as it does, such vital matters in company administration as change of name of the company, conversion of a public limited company

into a private limited company, company contracts, transfer of shares, creation of charges, class meetings, oppression and mismanagement, inspection of companies, reconstruction of a company, winding up of a company, preservation of records, foreign companies, translation of documents, payment of fees, etc., besides the procedure for making application to the Central Government and filing of forms and returns with the Registrar of Companies under various sections of the Act.

2. The first set of rules and forms was notified under the Act by the Companies (Central Government's General Rules and Forms, 1956). Apart from 67 separate forms prescribed under these rules, there are also about 40 other forms prescribed under 30 other rules framed under the Act. Criticisms have been voiced from time to time by companies, various professions, Chambers of Commerce and Industries and others that there are too many forms, a number of them could be easily dispensed with, even those which are essential are quite complex in their layout, style and design and are also quite often ambiguous, not self explanatory, or inconsistent, not infrequently calling for information, not directly relevant for the purposes of the Act. All these have led, it is said, to considerable difficulties in their understanding and compliance. A review of the forms prescribed under the various rules had already become long overdue and would have been undertaken but for the major pending legislations which came into force in February, 1975 and the appointment of the High Powered Expert Committee to review the Companies Act, soon thereafter. The High Powered Expert Committee which received representations from various Chambers of Commerce and professional bodies also felt that there was considerable scope for reducing the number of forms and eliminating some of the unnecessary details contained therein and had suggested that the matter of revision of forms should be taken up by the Government. Some of the forms prescribed under the Act may also undergo change eventually if the recommendations of this Expert Committee are accepted by the Government. It is however, difficult to anticipate, at this stage, the share in which the recommendations of the Committee would be finally accepted by the Government and the consequent change that the forms under various rules having a bearing on the Committee's recommendations would eventually entail. For the reasons stated above, it has become necessary to constitute a Committee to undertake a comprehensive review of the forms prescribed under the Act other than those which are likely to undergo change in terms of the recommendations of the High Powered Expert Committee.

3. Government, accordingly, hereby appoints a Committee to consider and report on the changes that should be made in the existing forms prescribed under the Companies Act, 1956 and rules framed thereunder in order to make the forms simpler and effective as well as answer to the requirements of administering the Act.

4. The Committee will be constituted as follows :—

Shri K.K. Ray	I.A.S. (Rtd.)	Chairman
1. Shri A. Neelakantan		Joint Secretary (Legal) Member, Department of Company Affairs.
2. Shri V. Rajaraman,		Chartered Accountant Member, Thakur Valdya-natha Iyer & Company.

3. Shri P. R. Mukhopadhyaya,	Secretary, Indian Duplicators Limited.	Member
Shri A. M. Chakraborty	Joint Director (Legal) Department of Company Affairs.	Secretary

5. The headquarters of the Committee will be at New Delhi and it will meet as and when necessary. The report of the Committee shall be submitted to the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs), not later than 30th June, 1979.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all the State Governments, Union Territories, Ministries and Departments of the Government of India, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Private and Military Secretaries to the President.

Ordered also that it be published in the Gazette of India Extraordinary.

P. KRISHNAMURTI, Secy.

